बलूचिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान की भारत ग्रस्तता (फिक्सेशन)

*डॉ. ध्रुबज्योति भट्टाचार्जी**

पाकिस्तान की चर्चा में न्यायेतर कैद, हत्या और लापता होने का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। मुशर्रफ के शासनकाल के दौरान लापता होने की ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई थीं, जिनका अब तक कोई हिसाब-किताब नहीं है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, "वर्ष 2010 में गृह मंत्रालय ने लापता होने के 965 ऐसे मामलों को स्वीकार किया, जिनके कुछ न कुछ रिकार्ड थे। हालांकि, परिवारों, मानवाधिकार समूहों और राज्य द्वारा आंकड़ों के संबंध में किए गए दावे भिन्न हैं, जिनकी संख्या 200 से लेकर 7000 तक है।"[1] लेकिन बलूचिस्तान की स्थिति न केवल इस राष्ट्र की घरेलू शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर सकती है, बल्कि इसके निकट तथा विस्तारित पड़ोस को भी अशांत कर सकती है।

हालांकि, विगत दो सप्ताहों में पाकिस्तान ने विशेषकर कराची और बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने तथा उन्हें अंजाम देने में भारत की बाह्य खुफ़िया निकायों की भूमिका के संबंध में अपने आरोपों पर फिर से जोर दिया है।

बलूचिस्तान का मुद्दा

पाकिस्तान बनने से पहले बलूचिस्तान अर्धस्वायत्त प्रांत की हैसियत रखता था। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे विशेष रूप से अपनी भाषा तथा संस्कृति पर गर्व है। बलूची जनसंख्या एक ऐसे क्षेत्र में फैली है, जिसमें पाकिस्तान व अफगानिस्तान के साथ-साथ ईरान के क्षेत्र शामिल हैं। पाकिस्तान में रह रही अधिकांश बलूची जनता 1950 के दशक की शुरूआत से ही संघीय सरकार के मनमाने शासन के विरूद्ध विरोध के स्वर उठाती रही है। प्रारंभ में, उन्होंने स्वतंत्र बलूचिस्तान राज्य तक की मांग की थी, लेकिन समय बीतने के साथ उनकी मांग अधिक स्वायत्ता तथा अधिक आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की रही है। बलूचिस्तान प्रांत की जनसंख्या लगभग 1 करोड 30 लाख (बलूचियों का 55 प्रतिशत) है, जिसमें केवल 23 प्रतिशत जनसंख्या शहरी केन्द्रों में बसी है और शेष खानाबदोश पशुपालन और स्थायी कृषि के मिले-जुले कार्यों से संबद्ध हैं। अधिकांश अर्थव्यवस्था गैर-बलूचियों द्वारा संचालित होती है और क्वेटा से बाहर के क्षेत्र अधिकांशतः संसाधन संपन्न प्रांत होने के बावजूद अविकसित और कामचलाऊ प्रबंध वाले हैं। चूंकि इस प्रांत की सीमाएं अफगानिस्तान से मिलती हैं, इसलिए छोटे हथियारों की बड़े पैमाने पर तस्करी होती है, जिससे विकेन्द्रित बलूची सशस्त्र स्वतंत्र समूह क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा बन

गए हैं। लेकिन सरकार की अकर्मण्यता और दमनकारी कार्यों ने जनता को हाशिए पर डाल दिया है, जिनके बीच निरक्षरता दर तथा असमानताएं देश में सर्वाधिक हैं। नौकरशाही व सरकार के साथ-साथ सेना में भी इनका प्रतिनिधित्व अत्यंत कम है। कुछ लोगों का यह दावा है कि ग्वाधर, जो कुछ समय से सुर्खियों में रहा है, की कमाई का केवल दो प्रतिशत बलूचियों को लाभ पहुंचाएगा, जबकि शेष कमाई चीनियों और संघीय सरकार के बीच में बंटेगी।[2]

स्मरणीय है कि वर्ष 2005 में प्रारंभ हुए बलूची आंदोलन का पांचवा प्रदर्शन सूई, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के किसी व्यक्ति द्वारा एक बलूची डॉक्टर के बलात्कार के बाद सक्रिय हुआ, जिसे कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। इस मामले को रफा-दफा करने के प्रयास के कारण रक्षा सुरक्षा (डिफेंस सिक्योरिटी) गार्डों और सीमांत सिपाहियों के विरूद्ध बड़े पैमाने पर हिंसा फैली।[3] उस समय पाकिस्तानी प्रतिनिधियों ने इस संघर्ष को प्रांतीय संसाधनों के बड़े हिस्से के लिए संघर्षरत स्थानीय जनजातीय नेताओं व लालची *सरदारों* की उपज बताया जो अपनी उन शक्तियों को बनाए रखने के लिए विकास का विरोध कर रहे थे, जो सामंती प्रणाली के पुराने अवशेष हैं।[4] आज वे आंदोलन और विद्रोह को सहायता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खुफ़िया एजेंसियों विशेषकर भारतीय एजेंसियों पर जोर-शोर से दोषारोपण कर रहे हैं।

पाकिस्तान की दमनकारी और मंददृष्टि से देखने की नीति

राजनैतिक विश्लेषकों ने कहा है कि, "पाकिस्तानी सुरक्षा संस्थान बलूची सामाजिक ढ़ांचे को नष्ट करने में अपेक्षाकृत रूप से प्रभावी साबित हुए हैं, लेकिन यह प्रांत पर अपने न्यायिक आदेश लागू करने या व्यवहार्य विकल्प संरचनाओं का प्रस्ताव रखने में असफल रहा है। इस बीच, सुरक्षा संस्थानों ने जातीय तनावों को अत्यधिक बढ़ा दिया है। अलगाववादियों ने न केवल पाकिस्तान की संघीय एजेंसियों पर, बल्कि गैर-बलोच जातीय पृष्ठभूमि वाले साधारण नागरिकों पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया है और कथित रूप से सुरक्षा तंत्र का इसके कट्टरपंथी परोक्ष/प्रॉक्सी समूहों पर नियंत्रण नहीं रहा है।"[5] वर्तमान में, अधिकांश स्थानीय पदाधिकारियों को डर है कि उनके फोन पाकिस्तानी खुफ़िया (एजेंसियों) द्वारा टैप किये जा रहे हैं,[6] और दो-पहिया वाहनों पर सवार हत्यारों की संख्या बढ़ती जा रही है; उनके निशाने पर कोई और नहीं, बल्कि वे लोग हैं जिन्हें इस आधार पर निशाना बनाया जाता है कि बलूचिस्तान आंदोलन में वे कितने सक्रिय हैं। यदि साबीन महमूद की हत्या का मामला लिया जाए तो अनेक विश्लेषक और मानवाधिकार कार्यकर्ता महमूद को हमेशा के लिए चुप कर देने में आईएसआई की भूमिका स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं।[7] यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "बलूच राजनैतिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता, अधिवक्ता, पत्रकार और छात्र नेता उन लोगों में शामिल हैं, जिन्हें बलात गायब करने, अपहरण, मनमानी गिरफ्तारी और उत्पीड़न तथा अन्य गलत व्यवहारों के लिए निशाना बनाया गया है। यह हिंसा बलूचिस्तान में बढ़ती राजनैतिक अशांति और पाकिस्तानी सैन्य अभियानों के संदर्भ में हो रही है।"[8]

विगत वर्षों में, बलूचिस्तान में सरकार के दमनकारी चालों में बदलाव आया है।[9] सैन्य अभियान रोक दिए गए थे, लेकिन सम्पूर्ण प्रांत में लोगों का अपहरण करके उनकी हत्या की गई और उनके शवों को लावारिस छोड़ दिया गया; ऐसे कृत्यों को मोटे तौर पर "मारो और फेंको" अभियान कहा गया। ये अभियान इस प्रांत को नियंत्रण में रखने और राज्य की शक्ति थोपने के प्रयास हैं। पाकिस्तानी सेना द्वारा बलूचिस्तान में अंजाम दिए गए बलात अपहरण की ठीक-ठीक संख्या ज्ञात नहीं है। बलूच राष्ट्रवादी दावा करते हैं कि ऐसे मामले "हजारों" की संख्या में हैं। वर्ष 2008 में गृहमंत्री रहमान मलिक ने कम से कम ग्यारह सौ शिकार व्यक्तियों का उल्लेख किया। लेकिन जनवरी 2011 में बलूचिस्तान के गृहमंत्री, जफ़रूल्ला जेहरी ने कहा कि केवल 55 व्यक्ति ही लापता हैं।[10]

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के 11 सितम्बर, 2012 के संपादकीय में संकेत दिया गया कि जनवरी 2012 से अब तक 57 लापता व्यक्तियों के शव पाए गए हैं। हालांकि, अन्य अखबारों ने इसी अवधि में सौ से अधिक लोगों के आंकड़ों का उल्लेख किया है। अगस्त 2012 की अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने संकेत दिया कि उसने जनवरी 2000 और 12 मई, 2012 के बीच बलूचिस्तान में बलात अपहरण के 198 मामलों की पुष्टि की थी और केवल वर्ष 2012 में ही बलूचिस्तान में लापता व्यक्तियों के 57 शव पाए गए थे।[11]

हालांकि सैन्य और खुफ़िया एजेंसियां ऐसे आरोपों का खंडन करती हैं, लेकिन पाकिस्तानी प्रेस भी बांग्लादेश युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा भर्ती किये गए अल शम्स और अल बद्र लड़ाकों की ही तरह बलूच गन्स-फॉर-हायर से बने मारक दस्तों के उपयोग की रिपोर्ट देता है।[12] खुफ़िया एजेंसियों ने कथित रूप से आज बलूचिस्तान में कार्यरत मारक दस्तों का गठन मारिस, मंगल और बुग्ती (कबीलों) में दुविधा पैदा करके और उनकी गतिविधियों में बाधा डालकर उनका मुकाबला करने के लिए किया। वे संभवतः जनजातीय नेताओं तक को भी बलूच राष्ट्रवादी के प्रतिनिधियों से बदल देंगे जो इस्लामाबाद के पूर्णतया अधीन होंगे।[13]

आंतरिक मामलों के मंत्री, चौधरी निसार अली खान ने हाल ही में सिंध में एक वक्तव्य में स्पष्ट किया, जब उन्होंने कहा कि जून 2014 के बाद से मुख्यतः खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 10,000 से भी अधिक खुफ़िया सूचना पर आधारित अभियान चलाए गए थे, जिनमें आतंकवाद तथा अतिवाद सहित गंभीर अपराधों के आरोपी लगभग 36,000 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और ये अभियान पुलिस तथा अन्य असैनिक बलों द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए थे।[14] मानवाधिकार पर्यवेक्षण द्वारा बलूचिस्तान में बलात अपहरण में सर्वाधिक संलिप्त सरकारी एजेंसियों में सैन्य खुफ़िया (एमआई), फ्रंटियर कोर (एफसी), और कुछ कम हद तक, अंतर सेवा खुफ़िया निदेशालय (आईएसआई) तथा खुफ़िया ब्यूरो (आईबी) शामिल हैं।[15]

निष्क्रिय कलात राज्य के राजकुमार और बलूच रबीता इत्तेफ़ाक तहरीक के प्रमुख, **प्रिंस मोहीउद्दीन बलोच** ने कहा, "आज हम ताकत का इस्तेमाल देखते हैं, क्षत-विक्षत शव वीराने में फेंक दिए जाते हैं, यहां तक कि मैं भी मारा जाता, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वर्तमान में बलूच की जनता जंग नहीं लड़ रही, बल्कि विरोध प्रदर्शन कर रही है और वे लोग भी जो पहाड़ की चोटियों पर चढ़े हैं, लड़ाई में शामिल नहीं हैं।"[16] कुछ वरिष्ठ बलूची नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि पाकिस्तानी सरकार दिसम्बर 2015 तक बलूची जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रहती है तो ऐसी संभावना है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाएगी।[17]

भारतीय खुफ़िया एंजेंसियों के विरूद्ध आरोप

यह निश्चय ही आश्चर्यजनक तथ्य है कि आरोप वरिष्ठ पाकिस्तानी सेना और राजनैतिक नेताओं द्वारा लगाए जा रहे हैं कि भारतीय खुफ़िया एजेंसियां उन कार्यकर्ताओं की हत्या और अपहरण में प्रत्यक्ष रूप से संलिप्त हैं, जो अवैध ताकत का इस्तेमाल करने; बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों के नागरिकों की उपेक्षा करने एवं उनकी ज़रूरतों को कुचलने; और पाकिस्तानी सरकार के विरूद्ध न्यायसंगत विद्रोही आंदोलन का गला घोंटने के लिए पाकिस्तानी सरकार पर दोषारोपण करते रहे हैं। जब कार्यकर्ताओं ने कराची में शांतिपूर्ण जलसा/सभा आयोजित करने का प्रयास किया तो कानून प्रवर्तक एजेंसियों ने सुरक्षा पर ऐसे खतरों के आधार पर इन जलसों को प्रतिबंधित कर दिया, जिन्हें स्पष्ट नहीं किया गया।

पाकिस्तानी सुरक्षा संस्थाओं का भारत-भय एक बार फिर सामने आया है, जब भारत एशिया में अपने निकट तथा विस्तारित पड़ोस के साथ द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार करने तथा उन्हें मजबूत बनाने के गंभीर प्रयास कर रहा है।

सरकारी पदाधिकारियों से लेकर मंत्रियों के साथ-साथ सेना के पूर्व जनरलों तक, पाकिस्तान ने भारत को हर संभावित तरीके से दोषी करार देने का एजेंडा तैयार कर लिया है।[18] उन नीतियों को, जो बलूचिस्तान तथा इसकी जनता के विकास को पूर्णतया दरकिनार करती है, जो इस प्रांत को गंभीर वार्ता की प्रक्रिया में शामिल करा सकती थी, उनको अनुकूल बनाने के बजाए उन्होंने बलूचियों को पृथक रखने और इस प्रांत से यथासंभव अधिक संसाधनों को निचोड़ने की नीति पर चलना जारी रखा है।

जनरल राहील शरीफ ने भारत के साथ शांति वार्ता में किसी भी प्रकार की प्रगति का लगातार विरोध करने का रूख अपनाया है। 1971 के युद्ध में अपने भाई, जो सीतारा-ए-जुरत और निशान-ए-हैदर दोनों का एक मात्र प्राप्तकर्ता था, को खोने के बाद इसने प्रारंभ से ही भारत विरोधी रूख अपना रखा है। यह जम्मू और कश्मीर में सक्रिय विभिन्न अतिवादी तथा हिंसक समूहों का कट्टर समर्थक रहा है।[19] हालांकि इसने *जर्ब-ए-अज्ब* अभियान को अंतिम रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन इसने भी भारतीय खुफ़िया संगठनों पर सीधा दोषारोपण करना प्रारंभ कर दिया है।[20]

पाकिस्तानी संस्थानों ने कई बार तर्क दिया है कि जारी घुसपैठ विदेशी सरकारों के निहित समर्थन के बिना जारी नहीं रह सकती थी। बलूच रिपब्लिकन आर्मी (बीआरए) में बुग्ती जनजाती के लड़ाके शामिल हैं। नवाब अकबर बुग्ती अथवा 'बलूचिस्तान का शेर' स्वयं भी इसी समुदाय का है, जो बलूची पहचान के लिए लड़ने वाले प्रमुख समर्थकों में से एक था। इसकी हत्या पाकिस्तानी सुरक्षाबलों द्वारा कर दी गई जबकि बलूचिस्तान के गवर्नर ने कहा कि 'नवाब बुग्ती को हानि पहुंचाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है क्योंकि वे एक सम्मानित हस्ती हैं और दण्ड़ दिए जाने के लिए तो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं।'[21] यह आरोप लगाया गया है कि बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख नवाब बुग्ती के पोते ब्रहमदगह बुग्ती को भारतीय खुफ़िया एजेंसियों से चोरी-छुपे समर्थन मिल रहा है। जनरल मुशर्रफ ने स्पष्ट रूप से कहा कि "मुझे पता है कि वे उन्हें धन मुहैया कराते हैं, वे कठिनाई पैदा करने के लिए उन्हें हथियार देते हैं और बलूचिस्तान में हमारी पीठ में छूरा घोपते हैं।"[22]

यह आरोप लगाया गया है कि बलूच रिपब्लिकन आर्मी (बीआरए) का गठन बाहरी सरकारों, विशेषकर अफ़गानिस्तान की सहायता से किया गया था। तर्क दिया जाता है कि अफ़गान सरकार ने बलूच रिपब्लिकन आर्मी (बीआरए) नेतृत्व को सुरक्षित आश्रय प्रदान किया; लड़ाकों को हथियार और प्रशिक्षण में सहायता दी; और बलूचिस्तान में पचास बलूच रिपब्लिकन आर्मी (बीआरए) शिविरों के लिए धन दिया।[23] वर्ष 2014 में, बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भारत के अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंध (रॉ) सैन्य अभियानों के चालीस प्रशिक्षण शिविर चलाकर इस प्रांत में कम तीव्रता वाले संघर्ष को प्रायोजित करता है। हालांकि, इस प्रांत में एक भी भारतीय एजेंट गिरफ्तार नहीं किया गया है और भारत और बलूचिस्तान के बीच सन्निहित साझी भूमि सीमा नहीं है, जिससे इस बात की संभावना न के बराबर है कि रॉ लड़ाकों को तस्करी से भारी हथियार मुहैया कराता है।[24]

तथापि, प्रधान मंत्री नवाज़ शरीफ और सेना प्रमुख जनरल रहील शरीफ ने अफगान प्राधिकारियों से रॉ को पाकिस्तान में अशांति फैलाने से रोकने के लिए कहा। इससे पहले, पाकिस्तान के विदेश सचिव, एज़ाज़ अहमद चौधरी ने एक समारोह के बाद संवाददाताओं से कहा कि रॉ पाकिस्तान में अशांति फैलाने में संलिप्त है।[25] पाकिस्तानी सरकार द्वारा अपनाई गई दृढ़ता देश की विदेश तथा राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों को संचालित करने की पाकिस्तानी सेना की बढ़ती इच्छा को प्रदर्शित करती है। यह एक ऐसे समय में भारत के विरूद्ध पाकिस्तान के दृढ़ रूख का संकेत देती है जब पाकिस्तानी सेना चीन के सहयोग से अफ़गानिस्तान में शांति के एक प्रमुख जमानतदार के रूप में उभर रही है, जबकि भारत अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ा रहा है और अपने सामान्य द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार-क्षेत्र से बाहर के देशों के साथ भी संबंध मजबूत कर रहा है।[26]

तथापि, बलूचिस्तान में विद्रोह की समस्या के संबंध में कोई आसान समाधान प्रतीत नहीं होता। पाकिस्तान के ही मीडिया विश्लेषकों ने कहा है कि पाकिस्तान में असैन्य तथा सैन्य नेतृत्व के पास आतंकवाद के संबंध में कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है। असैनिक तथा सैनिक दोनों ही नेतृत्व में आतंकवाद के मामले में सहमति है। दुर्भाग्य से यह सहमति नगण्य है अथवा संक्षिप्त है क्योंकि एक स्पष्ट एकीकृत प्रतिक्रिया नदारद है।"[27] भविष्य में जातीय-राष्ट्रीय विद्रोह जारी रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने संघर्ष के मूल कारणों को सुलझाने में कम रूचि दिखलाई है और संभवतः यह बलूच राष्ट्रीयता को इसके सभी स्वरूपों में मिटाना जारी रखेगा।[28]

बलूची हितों और आकांक्षाओं को कुचलना जारी रहने, क्षेत्रीय आर्थिक विकासात्मक कार्यकलापों में इस प्रांत के देशी लोगों को शामिल किये बिना उनके आर्थिक संसाधनों का दोहन करने, जिसके चलते यह राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय खुफ़िया एजेंसियों को विद्रोह के लिए दोष दे रहा है, के साथ ही बलूच आंदोलन पहले से ही अनुभवहीन राष्ट्र को एकीकृत करने के बजाय पाकिस्तानी समुदाय में दरार और गहरा कर देगा।

***

** डॉ. ध्रुबज्योति भट्टाचार्जी विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्येता हैं।*

समाप्ति नोट:

---

[1] "सबसे कड़वी व्यथा", एमनेस्टी इंटरनेशनल, मानवाधिकार सुरक्षा, सितम्बर 2011, पृ. 2, https://www.amnesty.org/download /Documents/.../asa330102011en.pdf

[2] "बलूचिस्तान 2012" ,विदेश नीति के लिए देश का संकेतक, कार्लेटन विश्वविद्यालय, द नॉर्मन पैटरसन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, 2012, http://www4.carleton.ca/cifp/app/serve.php/1397.pdf

[3] निकोलस डी क्रिस्टॉफ, "आतंक का एक और चेहरा', ओपी एड, *द न्यूयॉर्क टाइम्स*, 31 जुलाई, 2005, http://www.nytimes. com/2005/07/31/opinion/31kristof.html?_r=0

[4] फ्रेडेरिक गरारे, "बलूचिस्तान: राज्य बनाम राष्ट्र", अंतर्राष्ट्रीय शांति हेतु कार्नेगी बंदोबस्ती , दक्षिण एशिया, अप्रैल 2013, पृ. 3,: http://carnegieendowment.org/files/balochistan.pdf.

[5] पूर्वोक्त, पृ. 4.

[6] समीरा शकले, "बलूचिस्तान में गुप्त युद्ध",न्यू स्टेट्समैन, *29 जनवरी, 2013, http://www.newstatesman.com/world-affairs/2013/01/secret-war-balochistan.*

[7] मुग्धा वारियार, "क्या साबीन महमूद, कार्यकर्ता बलूचिस्तान के मुद्दे के लिए आईएसआई वाच के तहत पाकिस्तान में गोलियों का शिकार हुआ था?" *इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स*, 25 अप्रैल, 2015, ' http://www.ibtimes.co.in/was-sabeen-mahmud-activist-shot-dead-pakistan-under-isi-watch-balochistan-issue-630351

[8] सबसे कड़वी व्यथा", एमनेस्टी इंटरनेशनल, ओपी. सीआईटी. पृ. 3.

[9] मीर मोहम्मद अली ताईपुर, "अल्जीयर्स की लड़ाई में जीतना" *डेली टाइम्स*, 25 अप्रैल, 2010, http://archives. dailytimes.com.pk/editorial/ 25-Apr-2010/analysis-winning-the-battle-of-algiers-mir-mohammad-ali-talpur.

[10] ह्यूमन राइट्स वॉच, "हम आपको यातना दे सकते हैं, मार सकते हैं अथवा वर्षों तक जीवित रख सकते हैं: बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बलात गुमशुदगी", पाकिस्तान, 12 जुलाई 2011 http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/pakistan0711WebInside.pdf.

[11] "बलूचिस्तान में आशाएं, भय और अलगाव", पाकिस्तान का मानवाधिकार आयोग। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग के तथ्य-खोजी अभियान की रिपोर्ट (15-19 मई , 2012), लाहौर, पृ. 59-71, http://hrcp-web.org/hrcpweb/wp-content/pdf/ff/12.pdf.

[12] मुहम्मद अकरम, "बलूच नेताओं ने अपने मुद्दों को ठीक से रखा। *क्या कोई सुन रहा है?" डॉन*, 28 सितम्बर, 2012

[13] फ्रेड्रिक ग्रेर, ओपी. सीआईटी. पृ. 14

[14] "सरकार सफूरा गाथ के दोषियों को गिरफ्तार करने के बहुत करीब: निसार", डेली टाइम्स पाकिस्तान, *19 मई, 2015 http://www.dailytimes.com.pk/national/19-May-2015/govt-very-close-to-arresting-safoora-goth-culprits-nisar.*

[15] ह्यूमन राइट्स वॉच, ओपी. सीआईटी. पृ. 25

[16] "सरकार जल्दी ही बलूचिस्तान पर से सभी नियंत्रण खो सकती है", डॉन, 27 फ़रवरी, 2015, ' http://www. dawn.com/news/1166129 ।

[17] पूर्वोक्त।

[18] "कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान सेना ने 'भारत को गले से पकड़ा': परवेज मुशर्रफ", *द इकोनॉमिक टाइम्स।*

[19] नियाज़ मुर्तजा, "एक असफल राष्ट्र" , डॉन, *17 मई, 2015, ' http://www.dawn.com/news/1182400.*

[20] ' रॉ पाकिस्तान में आतंकवाद को उकसा रहा है : जनरल राहील", *पाकिस्तान ऑब्जर्वर*, 06 मई, 2015, http://pakobserver.net/detailnews.asp?id=263275.

[21] "पाकिस्तान: बलूचिस्तान में बदतर होता संघर्ष", अंतरराष्ट्रीय संकट समूह, एशिया रिपोर्ट, सं 119, 14 सितम्बर, 2006, पृ. 23

[22] " बलूचिस्तान में अशांति के लिए रॉ को दोषी मानते हैं मुशर्रफ", एनडीटीवी, *27 नवम्बर, 2010, http://www.ndtv.com/india-news/musharraf-blames-raw-for-unrest-in-balochistan-440413*.

[23] बी. मुहम्मद, "पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में राष्ट्रवादी उग्रवाद की गतिशीलता", विश्व संस्थान अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संबंध, 2014, पृ. 69,: http://www.imemo.ru/files/File/magazines/puty_miru/2014/April/06BilalBeludzhistan.

[24] ए बंसल, 'बलूचिस्तान में विद्रोह के लिए उत्तरदायी कारक", छोटे युद्ध और विद्रोह, खण्ड 19, अंक 2, 2008, पृ. 182-200.

[25] "रॉ को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान क्षेत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए, पाक विदेश मंत्रालय का कहना है", *बिजनेस स्टैंडर्ड, http://www.business-standard.com/video-gallery/world/raw-must-not-use-afghan-territory-against-pakistan-asks-pak-foreign-ministry-20756.htm* , 15 मई, 2015.

एम इलियास खान, "भारतीय आतंकवाद संबंधी पाकिस्तानी आरोप के पीछे की सच्चाई क्या है", *बीबीसी समाचार*,

[27] नियाज़ मुर्तजा, "एक असफल राष्ट्र" , डॉन, *17 मई, 2015, ' http://www.dawn.com/news/1182400.*

[28] डेनियल जे. लेबोविट्ज़, "क्यों जातीय-राष्ट्रवादी उग्रवाद बलूचिस्तान में 66 वर्षों तक चलता रहा है?", *भूरणनीतिक पूर्वानुमान*, http://www.geostrategicforecasting.com/wp-content/uploads/2015/01/Balochistan.pdf.